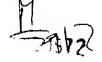


श्रामाधा गण

EXTRAORDINARY



भाग 1--धाण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਧ 3 102)

तई दि ली, सो तार ाई 8 1972, वंशाल 18, 1891

No 102]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 1972/VAISAKH \ 18, 1894

इस भाग में भिन्न (ष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के कर में रखा जा जह ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th May 1972

No. F.65(11)Ins.III/1/72.—As a first step towards the nationalisation of general insurance business, the management of the undertakings of insurance carrying on general insurance business (with certain exceptions) was taken over, with effect from the 13th May, 1971, under the General Insurance (Emergency Provisions) Act, 1971. Necessary legislation for the next step, namely, taking over the ownership will follow soon.

2. The terms and conditions of service of employees in general insurance vary widely. It is necessary that uniform pay scales and service conditions are evolved and all employees coming into the nationalised set-up integrated into them. Government have, therefore, decided to constitute a Committee to go into the matter

in all its aspects and make suitable recommendations. The Committee will consist of the following:—

- (1) Shri K. P. Mathrani, ICS(Retd)-Chairman.
- (2) Shri C. S. Anantapadmanabhan, Controller of Insurance-Member.
- (3) Shri B. G. Idnani-Member Secretary.
- 3. The following will be the terms of reference of the Commitee:-
- (i) (a) To examine the existing organisational and administrative set-up in general insurance business;
 - (b) to suggest the principles which should govern the pay-scales and other terms and conditions of service to be fixed for the nationalised set-up; and
 - c) to recommend suitable designations, integrated scales of pay and other terms and conditions of service in the nationalised set-up, having regard to the nature of work and levels of responsibility.
- (ii) To recommend the general and technical qualifications and also nature and length of experience for determining the eligibility of such employees for holding posts or specified categories of posts in the integrated set-up.
 - (iii) To recommend the criteria for-
 - (a) absorption of the employees of those insurers, the management of whose undertakings has been taken over by Government and also of other insurers and Government Departments whose general insurance business may be transferred to the nationalised set-up, against specific grades and scales of pay; and
 - (a) laying down the guidelines for the regulation of their seniority and scale of pay in such set-up taking into account, inter allia, their qualifications, experience, the levels of responsibility shouldered by them as also their record of performance.
- It is not not not the responsibility of Assistant Branch Managers or posts of corresponding category (whether on the administration or development side) and officials of higher rank or responsibilities who are in the employ of the insurers and departments referred to in sub-clause (iii) above, at what level each of such officials may be absorbed in the integrated set-up and the integrated set-up at various levels.
- (v) To make any other recommendations, incidental or aucillary to the foregoing which the Committee may deem fit.
- 4. The Committee will devise its own procedure for transacting its business and may call for such information and may take such evidence as it may consider necessary. It may also, in its discretion, interview any person who may be affected by any recommendation which the Committee is likely to make.
- 5. The Committee will have its Headquarters at New Delhi and will function as an attached officer of the Ministry of Finance. It has started functioning from 1st May, 1972.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all concerned and that be published in the Gazette of India for general information.

वित मंत्रालय

(राज्यस्य ग्रीए मीधा विभाग)

सं अत्य

नई दिल्ली, 8 मई, 1972

लं • फा • 65(11) वी T-III/1/72. — विविध बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रथम वरण के रूप में, विविध बीमा कारोबार चलाने वाले बीमा-उपक्रमों का प्रबन्ध, साझारण बीमा (आपात उपवन्ध) प्रक्षितियम 1971 के अन्तर्गत, (कुछ अपवादों को छोड़ कर) 13 मई, 1971 से सरकार में अपने हाथों में ले लिया था। स्वामित्व ग्रहण करने के प्रगले चरण के लिये आवश्यक विधान शीझ पेश किया जायगा।

- 2. विविध बीमा कम्पिनिमों के कर्मनारियों की सेवा की शर्ते वड़ी भिन्नताएं लिए हुए हैं। यह भावश्यक है कि एक रूप वेतनमान और सेवा की शर्ते तैयार की जायं, और राष्ट्रीयकृत संरचना के अन्तर्गत आने वाल सभी कर्मचारियों का उनमें समावेश किया जाय। इसलिये, इसे मामले में सभी पहलुओं से विचार करने और उपबुक्त सिफारिशों करने के लिये सरकार ने एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है। समिति में मिम्नलिखित हिम्मिलत होंगे :---
 - (1) श्री के बी विश्वपानी, आई वसी एस (सेवा निवृत्त) . ग्राध्यक्ष
 - (2) श्री ती एत अनन्तयक्ताभन्, बीमा निवन्त्रकः , . सदस्य

 - समिति में निर्वेश-षद निम्नलिखित होंगे :——
 - (i) (क) विविध सीमा कारोबार की वर्तभान संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना की जंग करना:
 - (ख) राष्ट्रीयक्कत सरचना के ग्रधीन वेतनमानों और सेवा की ग्रन्य शर्तों ग्राधि की क्वनस्था जिन सिद्धान्तों के श्रनुसार होनी चाहिये उनके बारे में सुझाब देना;
 - (ग) कार्य के स्वरूप और जिस्मेक्षारी के स्तरों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीयकृत संरचना में उपयुक्त पदनामों, एकीकृत वेतन-मानों और सेवा की अन्य शर्ती आदि के बारे में निकारिश करना।
 - (ii) एकीक्कत संरचना में, पदों में प्रथमा विनिर्दिश्ट पद-वर्गों में नियुक्ति के लिए कर्मचारियों की पाकता का निर्णय करने के प्रयोजन से सामान्य और तकनीकी ग्रर्शताओं की तथा प्रश्नम के स्वरूप एवं ग्रविध की भी सिफारिश करना।
 - (iii) निम्लालिकित के सम्बन्ध में मानदण्ड की सिफारिश करना—
 - (क) जिन बीया कम्पनियों की प्रवस्थ व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, उन के और जिन अन्य कीया कम्पनियों तथा यरकारी विभागों का विधिध बीमा कारोबार, राष्ट्रीयहृत संरचना की अन्तरित किया जाय, उनके भी कर्मचारियों का विधिष्ठ प्रेडों और केंग्न-मानों में समाचेश करना; भीत.

- (ख) श्रन्य बातों के साथ साथ, कर्मचारियों की योग्यताश्रों, श्रनुभय, उनके द्वारों वहन की गयी जिम्मेदारी के स्तरों श्रौर उनके कार्य-कोशल के रिकार्ड को दृष्टि में रखते हुए उक्त सरचना में उनकी बरिष्ठता तथा बेतनमानों के नियमन के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण:
- (iv) महायक शखा प्रबन्धक के पद पर प्रथवा उससे उच्चतर पद पर कार्य करने वाले श्रीर/प्रथवा उस पद अथवा उससे उच्चतर पद की जिम्मेदारियों को बहन करने वाले जो श्रिधिकारी उपर्युक्त खंड (iii) में उल्लिखित बीमा कम्पनियां श्रीर विभागों की नौकरी में (चाहे प्रशासन पक्ष में हो श्रयवा विकास पक्ष में) हैं, उनके सम्बन्ध में विशिष्टतः यह निफारिश करना की एकीकृत सरचना में ऐसे प्रत्येक श्रिधिकारी का किस स्तर पर समाहार किया जाए, श्रौर जिन कर्मचायों को एकीकृत सरचना में विशिष्ट स्तरों पर समाहित करने के लिए उपर्यक्त समझ। जाए उनकी परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण;
- (v) ऐसी भ्रन्य सिफारिशें करना जो उपयंक्त की प्रासंगिक भ्रथवा भ्रनुषंगी हों भ्रीर जिन्हें समिति, उपयुक्त सम्झें।
- 4. श्राने कार्य संचालन के लिए कार्यावधि , समिति स्वयं ही निश्चित करेगी तथा समिति ऐसा सूचना प्राप्त कर सकेगी एवं प्रेसा माक्ष्य ले सकेगी, जिसे वह श्रावण्यक समझें । वह श्रपने विवेकानुगार ऐसे किसी व्यक्ति की मुलाकात भी ले सकेगी जिस पर समिति झारा की जाने वाली किसी संभावित सिफारिश का श्रमर पड़ता हो ।
- 5. समिति अपना मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में रखेगी तथा विन मन्नालय के सम्बद्ध कार्याल (के रुप में कार्य करेगी । समिति ने 1 मई, 1972 से कार्य करना प्रार+म कर दिया है ।

म्रादेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतितिपि सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की भेज दी जायोतथा इसे श्राम भूचना के लिए भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाये।

> एम० आर० धादी, सचिव।